45,000 भारतीय कंटेनर फंसे

अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों पर भारतीय कंटेनर अटकने के कारण निर्यात लागत लगभग 5 गुना तक बढ़ी

शाइन जेकब और ध्रुवाक्ष साहा

नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में फंसे कंटेनर

पश्चिम एशियाई युद्ध का असर भारतीय निर्यातकों पर साफ दिख रहा है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के मुताबिक, लगभग 40,000-45,000 भारतीय कंटेनर फिलहाल या तो रास्ते में फंसे हुए हैं या अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों पर अटके हुए हैं। करीब 1-1.5 अरब डॉलर के निर्यात माल का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है, क्योंकि या तो इसके लिए मार्ग बदलना पड़ेगा या फिर भारत की ओर रुख करना पड़ेगा, जिससे लागत में और भी बढ़ोतरी होगी।

इसके अलावा, शिपिंग कंपनियों द्वारा लगाए गए कई आकस्मिक शुल्कों के कारण प्रति कंटेनर लागत में तीन से पांच गुने तक की वृद्धि हो रही है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इन सभी कारणों से लागत में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कंटेनर संकट की स्थिति पैदा हो सकती है और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के निर्यातकों को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, अटके हुए माल में बासमती चावल का एक बड़ा हिस्सा है, जो 4 लाख टन है।

संपूर्ण लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला सेवा प्रदाता कंपनी ट्राइटन लॉजिस्टिक्स ऐंड मैरीटाइम के मुख्य कार्याधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, 'भारतीय निर्यात से संबंधित लगभग 40,000-45,000 कंटेनर फंसे हुए हैं और उनमें से लगभग 80 प्रतिशत समुद्री मार्ग में हैं। मोटे अनुमानों के अनुसार, हवाई और समुद्री दोनों मार्गों पर लगभग 1-1.5 अरब डॉलर मूल्य का माल फंसा हुआ है।'

जल्दी खराब होने वाले सामान का निर्यात करने वालों के लिए इसका मतलब संपूर्ण नुकसान है। सूत्रों के अनुसार, युद्ध जोखिम अधिभार, जिनमें आपातकालीन लागत वसूली शुल्क (ईसीआरसी), आकस्मिक शुल्क और पीक सीजन शुल्क आदि शामिल हैं, निर्यातकों के मुनाफे को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। श्रीवास्तव ने बताया कि कई निर्यातक बैक-टू-टाउन (बीटीटी) विकल्प के लिए आवेदन करने पर विचार कर रहे हैं। यह एक सीमा शुल्क प्रक्रिया है जो निर्यातकों को निर्यात प्रक्रिया में शामिल होने के बाद बंदरगाह से माल वापस लेने और उसे घरेलू बाजार में वापस लाने की अनुमति देती है।

व्यापार नीति विश्लेषक एस चंद्रशेखरन ने कहा, 'ये आंकड़े सही प्रतीत होते हैं। हालांकि, निर्यातकों को प्रति कंटेनर 3,000-5,000 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ रहा है, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। यह उच्च जोखिम लागत के कारण हो रहा है। अरब सागर में माल ढुलाई भी अब जोखिम भरी हो गई है।' यह उसी मार्ग पर सामान्य दिनों में प्रति कंटेनर 800-1,500 डॉलर की मौजूदा औसत माल ढुलाई लागत के अतिरिक्त है।

होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने के एक दिन बाद फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी सीएमए सीजीएम ने आपातकालीन अधिभार लागू किया, जिसके तहत माल ढुलाई पर 2,000-4,000 डॉलर का अधिभार लगाया गया। बाद में अधिकांश प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने यह अधिभार लागू कर दिया। एक फ्रेट फॉरवर्डर के अनुसार, बीमाकर्ताओं द्वारा युद्ध जोखिम कवर को रद्द करना भी उद्योग के लिए एक समस्या बन गया है। कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन (सीएसएलए) के सुनील वासवानी ने कहा, 'कुछ कंटेनर या तो समुद्र में हैं या आसपास के बंदरगाहों पर अटके हुए हैं। यह एक तरह की अप्रत्याशित घटना है और अगर खाड़ी देशों में माल उतारने की संभावना नहीं है, तो वे सलालाह जैसे बंदरगाहों पर माल उतार सकते हैं या भारत लौट सकते हैं।' उन्होंने कहा कि फंसे हुए कंटेनरों की संख्या लगभग 35,000 हो सकती है।

माल की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग कंपनियां परिवहन के विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रही हैं। उद्योग जगत के एक सूत्र के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े टर्मिनल संचालकों में से एक, डीपी वर्ल्ड ने अपने ग्राहकों को इस व्यवस्था के बारे में सूचित कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत, ग्राहक आयात कंटेनरों को खोरफक्कन बंदरगाह या फुजैराह बंदरगाह पर उतार सकते हैं। डीपी वर्ल्ड, शिपिंग कंपनियों और संबंधित अधिकारियों के समन्वय से अंतिम मंजूरी के लिए कंटेनरों को बॉन्डेड रोड ट्रांजिट के माध्यम से जेबेल अली बंदरगाह तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि फंसे हुए कई कंटेनर भारतीय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनमें फारस की खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले कई बगैर जहाज के संचालन करने वाले सामान्य वाहक (एनवीओसीसी) ऑपरेटर शामिल हैं। उद्योग के एक सूत्र के अनुसार, एनवीओसीसी के पास जहाज भले ही न हों, लेकिन ये कंटेनर उन्हीं के स्वामित्व में हैं।

वासवानी ने कहा, 'अतिरिक्त शुल्क अलग-अलग लाइनों पर अलग-अलग हैं। ये अतिरिक्त शुल्क हमारी परिचालन लागत का हिस्सा हैं। ये असाधारण परिस्थितियां हैं, इसलिए हम सामान्य शुल्क नहीं लगा सकते। पिछले पांच वर्षों में माल ढुलाई दरें पहले ही 70-80 प्रतिशत तक कम हो चुकी हैं।'

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष ए. शक्तिवेल ने कहा कि उनके उद्योग को फिलहाल किसी तरह के सरचार्ज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'कंटेनरों को अब एक चक्कर लगाकर जाना होगा, इसलिए हमारे लिए माल ढुलाई दरें 40 प्रतिशत बढ़कर लगभग 200 रुपये प्रति किलोग्राम से 280 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं।' इस बीच, भारत का पोत परिवहन मंत्रालय देश भर के बंदरगाहों पर माल के जमावड़े पर कड़ी नजर रख रहा है। सूत्रों के मुताबिक, भारत के सरकारी बंदरगाहों पर करीब 20,000 कंटेनर फंसे हुए हैं या उन्हें खाली कराने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

प्रमुख बंदरगाहों पर लगभग 7 लाख टन तरल माल निकासी की प्रतीक्षा में है और जल्द खराब होने वाला 939 टन माल फंसा हुआ है। मामले से परिचित एक सूत्र ने बताया, 'बंदरगाह माल की सुगम आवाजाही के लिए बीटीटी प्रावधानों से संबंधित नियमों और शुल्कों में ढील देने पर विचार कर रहे हैं।'

इस बीच, समुद्री खुफिया फर्म ड्रूरी के अनुसार, यदि संकट लंबा चलता है तो इस संकट के कारण माल ढुलाई की मूल दरों में भी भारी वृद्धि होने की आशंका है। उसने कहा कि हालांकि दरें फिलहाल अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन यदि जहाज और खाली उपकरण लंबे समय तक चक्कर लगाते रहते हैं तो बंदरगाहों पर भीड़भाड़, मार्ग परिवर्तन और परिचालन संबंधी समायोजन धीरे-धीरे प्रभावी क्षमता को कम कर सकते हैं।

फर्म ने कहा, 'शिपर्स के लिए, तत्काल प्रभाव सीमित हो सकता है, लेकिन निरंतर व्यवधान के कारण पारगमन समय बढ़ सकता है, क्षमता कम हो सकती है और प्रमुख पूर्व-पश्चिम गलियारों में माल ढुलाई दरों में अस्थिरता आ सकती है।'

गैस आपूर्ति के लिए कई मोर्चों पर काम, उर्वरक पर संकट नहीं

संजीव मुखर्जी

6 मार्च तक देश में 1.77 करोड़ टन उर्वरक भंडार

सरकार ने उर्वरक कंपनियों को आश्वासन दिया है कि वह पश्चिम एशिया से एलएनजी आपूर्ति में कमी से धीरे-धीरे निपटने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, ताकि युद्ध लंबा चलने पर भी कृषि उत्पादन में कोई बाधा खड़ी न हो।

सूत्रों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने प्रमुख उर्वरक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई सिलसिलेवार बैठकों में यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि केंद्र एलएनजी उपलब्धता को सुचारू बनाए रखने के लिए हर संभवना टटोल रही है। इसकी कमी को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने एवं बाद में योजनाबद्ध तरीके से और कम करने का प्रयास किया जाएगा। ये बैठकें ऐसे समय हो रही हैं जब विभिन्न स्रोतों से रिपोर्टें आनी शुरू हो गई हैं कि गेल ने नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की कुछ इकाइयों को एलएनजी आपूर्ति में 10 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है। इससे यदि और आपूर्ति में कटौती की गई तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार एलएफएल देश में यूरिया के कुल वार्षिक उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान देती है।

सूत्रों ने कहा कि कुछ सरकारी विभाग एक जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। इसे हालात को समझने और उसी आधार पर संभावित विकल्पों पर काम करने के लिए वित्त मंत्रालय समेत अन्य हितधारकों के साथ साझा किया जा सकता है।

कुछ सूत्रों ने कहा कि नीति आयोग को उर्वरकों और गैस उपलब्धता में मांग एवं आपूर्ति की स्थिति पर काम करने के लिए भी कहा गया है। जरूरत पड़ने पर उससे हस्तक्षेप करने की बात कही गई है। एक सूत्र ने कहा, 'उर्वरक क्षेत्र के लिए गैस उपलब्धता वर्तमान में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, ताकि युद्ध लंबा चला तो कृषि क्षेत्र के समक्ष कोई संकट पैदा न हो।'

व्यापार सूत्रों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2025 में लगभग 70 प्रतिशत यूरिया, 42 प्रतिशत डीएपी, 83 प्रतिशत अमोनिया और 60 प्रतिशत एलएनजी खाड़ी देशों से आयात की है। पिछले साल लगभग 56.5 करोड़ टन यूरिया, 45.7 करोड़ टन डीएपी और 25.4 करोड़ टन अमोनिया का आयात किया गया।

जहां तक एलएनजी का सवाल है, तो 60 प्रतिशत आयात में से अधिकांश कतर से आता है, जिसने युद्ध के कारण अब आपूर्ति रोक दी है। प्राकृतिक गैस को ठंडा कर एलएनजी में बदला जाता है। इससे इसकी मात्रा कम हो जाती है और इसे दूरदराज ले जाने में आसानी हो जाती है। बंदरगाहों पर पहुंचने पर एलएनजी को उर्वरक, बिजली, सिटी गैस और अन्य उद्योगों में उपयोग के लिए रिगैसिफिकेशन प्रक्रिया के जरिए गैस में परिवर्तित किया जाता है। सूत्रों ने कहा कि यूरिया बनाने में लगभग 80 प्रतिशत कच्चा माल गैस है। गैस आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट से भारत में यूरिया का घरेलू उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है और आयात पर इसकी निर्भरता बढ़ जाएगी। घरेलू खपत में वृद्धि के कारण भारत ने अप्रैल-जनवरी 2025-26 में लगभग 83 प्रतिशत अधिक यूरिया का आयात किया है। संकट शुरू होने के एक सप्ताह बाद से ही वेस्ट एशिया में यूरिया की कीमतें लगभग 100 डॉलर प्रति टन बढ़कर लगभग 600 डॉलर प्रति टन हो गई हैं, जबकि डीएपी की दरें भी प्रति टन 650-670 डॉलर से बढ़कर लगभग 750-770 डॉलर प्रति टन हो गई हैं।

केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा था कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे अगली फसल के लिए अपने खेतों की तैयारी शुरू करें, क्योंकि 6 मार्च तक देश में 1.77 करोड़ टन के बराबर उर्वरक भंडार मौजूद है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1.29 करोड़ टन से 36.5 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि डीएपी भंडार का अनुमान 25.1 लाख टन है। एनपीकेएस भी 55.8 लाख टन है जबकि यूरिया लगभग 60 लाख टन भंडारों में पड़ा है।

व्यापारियों ने कहा कि कुछ कंपनियों ने खाद्य पदार्थों की पैकिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन बैग की कीमत बढ़ा दी है। पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन दोनों में प्लास्टिक में पेट्रोकेमिकल उत्पादों का इस्तेमाल होता है।

भारत को करना होगा अपनी तेल भंडारण क्षमता का आकलन

एस दिनकर

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध में लगातार बदलते हालात और भारत के पेट्रोलियम भंडार एवं आयात रणनीति पर संभावित प्रभाव के बीच भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा का आकलन करना होगा कि उसकी क्षमता क्या है और कितनी जल्दी ईंधन भंडारों को दोबारा भरा जा सकता है। फिलहाल भारत के रिफाइनर वैकल्पिक सप्लाई के लिए ग्लोबल ट्रेडर्स और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं।

तेल भंडार रणनीतिक और वाणिज्यिक दो श्रेणियों में बंटे होते हैं। बाद वाले को रिफाइनरियों और डिपो में रखा जाता है जिनकी डिलिवरी आमतौर पर स्थानीय स्तर पर होती है जबकि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं। विश्लेषक और तेल मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर गणना के अनुसार भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार केवल पांच से छह दिनों की खपत के लिए पर्याप्त हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत के दो रिजर्व अपेक्षाकृत भरे हुए हैं, जबकि मैंगलोर सुविधा लगभग आधी भरी है। कुल 1.83 करोड़ बैरल की क्षमता वाला सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार- पादुर लगभग 82 प्रतिशत भरा है। मैंगलोर भंडार अपनी 1.1 करोड़ बैरल क्षमता से थोड़ा कम 50 प्रतिशत रखता है, जबकि 97 लाख बैरल क्षमता वाला विशाखापत्तनम भंडार पूरा भरा हुआ है। सरकार ने भंडारण डेटा को अलग नहीं किया है, लेकिन कहा है कि भारत के पास आठ सप्ताह के लिए पर्याप्त क्रूड ऑयल और ईंधन भंडार मौजूद है। रणनीतिक भंडार के विपरीत, वाणिज्यिक भंडार- जिसमें 25 दिनों का क्रूड ऑयल और 25 दिनों का ट्रांसपोर्ट फ्यूल शामिल है, स्थिर नहीं हैं। दो वरिष्ठ रिफाइनिंग अधिकारियों ने कहा कि रिफाइनरियों और आयात टर्मिनलों पर क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंक को आयात के माध्यम से लगातार दोबारा भरना होगा, क्योंकि वे फिलहाल चालू हैं। अधिकारियों ने इंटरनैशनल एनर्जी एजेंसी के एक दिलचस्प आंकड़े की ओर इशारा किया, जिसके अनुसार 2025 में वैश्विक तेल भंडार में 47 करोड़ बैरल या 13 लाख बैरल प्रति दिन (बीपीडी) की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि आपूर्ति में कोई कमी नहीं है।

केप्लर और यूके बाजार सूचना प्रदाता एनर्जी इंटेलिजेंस के अनुसार खुले समुद्र में टैंकरों में 13 करोड़ बैरल रूसी क्रूड, 3-4 करोड़ बैरल वेनेजुएला का तेल और फरवरी में भेजे गए 7 करोड़ बैरल से अधिक स्वीकृत ईरानी तेल का अधिकांश हिस्सा अभी जमा है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत के रिफाइनर वैकल्पिक सप्लाई के लिए ग्लोबल ट्रेडर्स और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं।

शिप-ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि भारतीय बंदरगाहों, रिफाइनरियों और टैंकों तक पहुंचने के लिए फरवरी में होर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाले लगभग 28 लाख बीपीडी पश्चिम एशियाई क्रूड ग्रेड को बदलने की आवश्यकता है।

ईरान के तेल भंडार पर हमला, बहरीन का जल संयंत्र उड़ाया

पश्चिम एशिया में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में रविार की रात एक तेल भंडारण इकाई पर हमला किया गया। इजरायल की सेना ने पुष्टि की कि उसने तेहरान में ईंधन भंडारण केंद्रों पर हमला किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध में पहली बार किसी असैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया है। इजरायल ने लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं और साइप्रस से लेकर श्रीलंका के तटवर्ती जलक्षेत्र तक हमले होने की खबरें हैं। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अपने पड़ोसी देशों पर मिसाइल एवं ड्रोन दागे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने नौ दिन पुराने अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, जिसका असर पूरे क्षेत्र में फैल चुका है और फिलहाल इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज करने की धमकी दी।

बहरीन ने आरोप लगाया है कि ईरान के ड्रोन हमले से उसके एक जल संयंत्र (विलवणीकरण संयंत्र) को नुकसान पहुंचा है। नौ दिनों के युद्ध के दौरान पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी विलवणीकरण (खारे पानी को पीने योग्य बनाना) संयंत्र को निशाना बनाया गया है। फारस की खाड़ी के तट पर सैकड़ों विलवणीकरण संयंत्र स्थित हैं और इस क्षेत्र के अरब देश पीने के पानी के लिए इन संयंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के नौवें दिन इजरायल ने रविवार तड़के दक्षिणी लेबनान पर हमले तेज कर दिए और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के अगले चरण में कई आश्चर्यजनक कदम उठाए जाने की चेतावनी दी।

लेबनान में हुए हाल के हमलों में 12 और लोग मारे गए है, जिससे वहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई है। उसकी सेना ने कहा कि यह हमला ईरान समर्थित बलों को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया था। इससे पहले इजरायल ने लेबनान के बड़े हिस्से को खाली करने का आदेश दिया था।

इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत करते हुए कहा था कि उन्होंने ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को निशाना बनाने तथा सरकार को गिराने की कोशिश करने के लिए हमले किए। इसके बाद ईरान ने भी

ईरान के तेहरान में तेल भंडार पर हमले के बाद नष्ट टैंकर

जवाबी हमले किए। इस युद्ध का व्यापक पैमाने पर असर दिख रहा है, वैश्विक बाजार हिल गए हैं, हवाई यात्रा बाधित हुई है और सैकड़ों इजरायली एवं अमेरिकी हवाई हमलों से ईरान का नेतृत्व कमजोर हो गया है।

ईरान के नेताओं ने जोर देकर कहा कि तेहरान की युद्ध रणनीति नहीं बदलेगी। युद्ध में तनाव कम करने की कोशिश करने वाले नेताओं और अमेरिका एवं इजरायल से लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध अन्य कट्टरपंथियों के बीच मतभेद किसी भी कूटनीतिक प्रयास को जटिल बना सकते हैं। युद्ध के दौरान शुरुआती हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद से ईरान की निगरानी कर रही नेतृत्व परिषद के तीन सदस्यों में से दो की ओर से परस्पर विरोधी बयान आए। पेजेश्कियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग खारिज कर दी। पेजेश्कियान ने कहा, 'यह एक ऐसा सपना है, जिसे उन लोगों को अपने साथ कब्र में ले जाना चाहिए।'

पेजेश्कियान के संदेश के तुरंत बाद, ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी कि युद्ध में और भी ईरानी अधिकारी निशाने पर आएंगे।

इस बीच, पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य कर्मियों एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान के साथ रूस द्वारा सूचना साझा करने की खबरों को अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने शनिवार को तवज्जो नहीं दी।

अमेरिकी और इजरायल द्वारा ईरान पर युद्ध शुरू करने के एक दिन बाद कुवैत में ड्रोन हमले में मारे गए सेना के छह सैनिकों के राजकीय सम्मान से हुए अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सूचना साझा करने संबंधी इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया।

पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में एक तेल भंडारण सुविधा के ऊपर आग की लपटें उठती दिखीं। इजरायल की सेना ने पुष्टि की कि उसने तेहरान में ईंधन भंडारण केंद्रों पर हमला किया। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध में पहली बार किसी असैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया है।

सरकारी मीडिया ने राजधानी और उत्तर में पड़ोसी प्रांतों को आपूर्ति करने वाले इस केंद्र पर हमलों के लिए 'अमेरिका और यहूदी शासन' को जिम्मेदार ठहराया। नेतन्याहू ने शनिवार रात कहा कि ईरान में युद्ध के अगले चरण के लिए इजरायल के पास कई आश्चर्यजनक कदमों की एक सुनियोजित योजना है। **भाषा**

पश्चिम एशिया में लड़ाई से प्रभावित हो रहा है ब्रांड दुबई

अक्षरा श्रीवास्तव और प्राची पिसाल

पश्चिम एशिया में चल रहे सैन्य संघर्ष का असर केवल व्यापार मार्गों और कच्चे तेल की कीमतों पर ही नहीं पड़ा है, इससे ब्रांड दुबई भी प्रभावित हो रहा है। ईरान की ओर से कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में चुनिंदा हमले किए जाने से यहां अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। इसका सबसे अधिक असर दुबई पर पड़ा है, जो लंबे समय से अपने गोल्डन वीजा और अनुकूल कराधान नीतियों की वजह से वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित जगह और प्रवासियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि दुबई इन हालात से बहुत जल्द उबर आएगा।

फ्यूचरब्रांड्स में ब्रांड विशेषज्ञ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष देसाई ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'दुबई पर हाल फिलहाल जरूर असर दिख रहा है, लेकिन इस ब्रांड की छवि पर लंबे समय तक बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अरबी रेगिस्तान के बीच स्थित दुबई को एक शांत जगह के रूप में जाना जाता है, जो जीवंत और सुरक्षित है। यहां वह सब कुछ जो प्रवासियों को लुभाने के जरूरी होता है।' उन्होंने कहा, 'भले ही पश्चिम एशिया में उथल-पुथल रही है, लेकिन दुबई इससे ज्यादातर अछूता ही रहा है। लेकिन मौजूदा युद्ध का लोगों पर गंभीर असर पड़ा है। कहा जाता है कि मनोविज्ञान और भूगोल एक समान नहीं होते। जब आसपास लड़ाई छिड़ी हो तो भले ही कोई इसमें सीधे तौर पर शामिल न हो, लेकिन उस पर असर अवश्य पड़ता है।'

दुबई, यूएई महासंघ बनाने वाले सात संप्रभु अमीरातों में से एक है, जो दुनिया में सबसे अधिक 6 से 9% किराया लाभ देता है। यहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, जो सबसे बड़ा विदेशी निवेशक समूह है।

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, दक्षिण दिल्ली, 4वां तल, 7, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली–110066 ईमेलः cs4168@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,
आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नामः / खाते का नामः / उधारकर्ता/गारंटर/ खाते का नाम और पताः	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(A) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (B) मांग सूचना के अनुसार राशि (C) सरफैसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (D) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.
1	(पूर्व में ए–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली) मेसर्स मनेरी आइसक्रीम (उधारकर्ता) ई–94, जीएफ, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048 मेसर्स मनेरी आइसक्रीम, प्लॉट नंबर–42, औद्योगिक क्षेत्र फूड पार्क, मनेरी जिला मंडला (एमपी)– 481885 सुश्री अनामिका मित्तल, (मालिक) एच नंबर– ई–94, जीएफ, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048	साम्यिक बंधक/पंजीकृत बंधक परियोजना भूमि एवं भवन पर, क्षेत्रफल 3300 वर्ग मीटर, प्लॉट सं. 42, फूड पार्क–मंडला, मनेरी, जिला मंडला में स्थित (मेसर्स मनेरी आइसक्रीम के नाम पर एक नामित फूड पार्क जबलपुर, मध्य प्रदेश, उपरोक्त इकाई में प्लांट एवं मशीनरी के साथ	A) 09.05.2022 B) Rs. 544.47 लाख + ब्याज + प्रभार इत्यादि C) 14.12.2022 D) सांकेतिक	A) रु. 374.20 लाख B) रु. 38.00 लाख (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) 26.03.2026 C) रु. 1,00,000/- लाख	27.03.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	संपत्ति पर कोई रोक नहीं है	श्रीमती ट्विंकल नैन 9802927574
2	(पूर्व में ए–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली) मेसर्स पारस मिल्क एंड फूड कॉर्पोरेशन (उधारकर्ता) पंजीकृत कार्यालयः बीबी–17, बेसमेंट, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव ।।, नई दिल्ली–110048 मेसर्स पारस मिल्क एंड फूड कॉर्पोरेशन फैक्ट्रीः प्लाट नंबर–43, इंडस्ट्रियल एरिया फूड पार्क, मनेरी, जिला मंडला, मध्य प्रदेश–481885 श्री पवनदीप छाबड़ा (प्रो.) पारस होटल, राईट टाउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश–482001 श्री पवनदीप छाबड़ा 1415 (366), मदन महल, गुप्तेश्वर रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश–482003 श्री अवदेश मित्तल (गारंटर) मकान नं. ई–94, जीएफ, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048	साम्यिक बंधक/पंजीकृत बंधक परियोजना भूमि एवं भवन पर, क्षेत्रफल 3300 वर्ग मीटर, प्लॉट सं. 43, फूड पार्क–मंडला, मनेरी, जिला मंडला में स्थित (मेसर्स पारस मिल्क एवं फूड कार्पोरेशन के नाम पर एक नामित फूड पार्क जबलपुर, मध्य प्रदेश, उपरोक्त इकाई में प्लांट एवं मशीनरी के साथ	A) 08.02.2023 B) Rs. 295.80 लाख + ब्याज + प्रभार इत्यादि C) 10.08.2023 D) सांकेतिक	A) रु. 582.47 लाख B) रु. 60.00 लाख (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) 26.03.2026 C) रु. 1,00,000/- लाख	27.03.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	संपत्ति पर कोई रोक नहीं है	श्रीमती ट्विंकल नैन 9802927574

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तो के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई–नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (**https://baanknet.com**) ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220), द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तो और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल **(1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in** पर उपलब्ध/प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75: जमा करने/बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ क्र. सं. 01 से क्र. सं. 02 तक के सभी मामलों में जारी किया गया है, (8) बिक्री की विस्तृत शर्तो के लिए, कृपया **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें।

दिनांक : 07.03.2026, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक